

बिहार ग्रिड कंपनी बनी, आने वाले दिनों में नहीं होगी बिजली किल्लत

बिजली सप्लाई अब बिना बाधा

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

आने वाले वक्त में राज्य में संचरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड बनाई गई है। यह कंपनी बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) और पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) की संयुक्त उपक्रम होगी। इसके लिए करार पर दस्तखत शनिवार को बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक टुनटुन झा और पावरग्रिड के कार्यकारी निदेशक (बीडीडी) अरुण कुमार ने किए। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, बीएसपीएचसीएल के सीएमडी पीके राय, पावरग्रिड के सीएमडी आरएन नाइक और अन्य प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे। इसे शुरू करने के लिए कंपनी द्वारा 6300 करोड़ रुपए की परियोजना प्रस्तावित है। पहले से घोषित कार्यक्रम के तहत यह करार राजगीर में होना था मगर बाद में इसे पटना में बीएसपीएचसीएल के सभाकक्ष में अंजाम दिया गया।

श्री यादव ने कहा कि 12 वीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2012 से 17) के अंत तक राज्य को विभिन्न स्रोतों से लगभग 10 हजार मेगावाट बिजली की उपलब्धता होगी इसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए जिस ट्रांसमिशन नेटवर्क की जरूरत होगी उसके लिए यह करार किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कृषि क्षेत्र और अन्य जरूरतों के मद्देनजर बिजली की मांग काफी बढ़ेगी। इसे पूरा करना मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में है। अभी अधिकतर ग्रिड पुरानी तकनीक पर

6300 करोड़ की है परियोजना

- बीएसपीएचसीएल और पावरग्रिड का है ज्वाइंट वेंचर, दोनों की होगी बराबर की हिस्सेदारी
- उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने के लिए बनी कंपनी : ऊर्जा मंत्री



परियोजना की खास बात

बिहार ग्रिड कंपनी बराबर की हिस्सेदारी (50:50 फीसदी की अंशधारक) और पूंजीनिवेश पर काम करेगी। दोनों कंपनियों के बीच नई कंपनी के गठन का एकरारनामा 25 वर्षों के लिए किया गया है। इसमें दोनों के निदेशकों की संख्या भी बराबर होगी। इसके द्वारा राज्य के ट्रांसमिशन सेक्टर में इन्हें से टेको मैनेजेरियल एक्सपोर्ट्स का समावेश होगा। इसके लिए ट्रांसमिशन का लाइसेंस और टैरिफ का निर्धारण बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाएगा।

बिहार ग्रिड को करने होंगे कई काम

बीएसपीएचसीएल और पावरग्रिड के संयुक्त उपक्रम में बनी नई बिहार ग्रिड कंपनी के सामने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अगले पांच साल (वर्ष 2012 से 2017 तक) के दौरान संचरण के क्षेत्र में कई काम करने होंगे। प्रस्तावित कार्यों में पार्ट-1 बिहार सब ट्रांसमिशन फेज-2 विस्तार योजना, पार्ट-2 (ए) के तहत फेज-1 में अगले तीन साल यानी वर्ष 2015 तक नई संचरण सुदृढीकरण का कार्य करना है। इसके साथ ही पार्ट-2 (बी) के फेज-2 के तहत वर्ष 2015-16 और 16-17 के बीच संचरण व्यवस्था के अलावा सुदृढीकरण का काम करना है। वहीं 132 केवी-430 किमी (10 की संख्या में) रिंकडविटिंग-द्वितीय परिपथ का कंडक्टर लगाना है। पार्ट-3 में जेनरेशन लिंकड योजना के तहत लखीसराय, पीरपैती और बक्सर में प्रस्तावित बिजली उत्पादन गृहों एवं केन्द्रीय प्रक्षेत्र से उपलब्ध होने वाली बिजली का दोहन वर्ष 2012 से 2017 के दौरान किए जाने वाले संचरण के नए कार्य किए जाएंगे। इसके तहत कई अन्य प्रमुख कार्य भी इसके जिम्मे होंगे।

आधारित हैं। ट्रांसमिशन के लिए नई कंपनी इसलिए बनानी पड़ी कि लगभग 4500 मेगावाट बिजली की उपलब्धता तो वर्ष 2015 तक ही बिहार में हो जाएगी। हम केवल आगामी चुनाव के लिए नहीं बल्कि इससे आगे के लिए सोच रहे हैं जब बिहार को सरप्लस बिजली

मुहैया रहेगी। हम बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन और उत्पादन के लिहाज से तो ठीक स्थिति में होंगे मगर दिक्कत संचरण में आनी है। इसलिए इसकी व्यवस्था करनी होगी। भविष्य में हाइडल क्षेत्र की बिजली का रूट भी बिहार से ही होकर जाएगा। इससे बिजली हासिल करने के लिए हमें

अगले पांच साल का लक्ष्य

नई लाइनें :

- 400 केवी : 300 किमी (चार की संख्या में)
- 220 केवी : 2200 किमी (31 की संख्या में)
- 132 केवी : 1550 किमी (33 की संख्या में)

नए ग्रिड उपकेन्द्र

- 400 केवी (तीन की संख्या में)
- 220 केवी (15 की संख्या में)
- 132 केवी (एक)

ट्रांसमिशन क्षमता

- नई व क्षमता विस्तार
- 11620 एमवीए
- कुल लागत
- 4400 करोड़ (लगभग)

संचरण नेटवर्क निर्माण

लागत (लगभग)

- पार्ट-1 300 करोड़
- पार्ट-2 (ए) 1400 करोड़
- पार्ट-2 (बी) 3000 करोड़
- पार्ट-3 1600 करोड़
- कुल 6300 करोड़

तैयार रहना होगा। इसके लिए हमने इस क्षेत्र में पावरग्रिड की विशेषज्ञता का लाभ लेने का निर्णय लिया है। वहीं बीएसपीएचसीएल से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2017 तक राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने के लिए लगभग 14 हजार करोड़ रुपए की जरूरत होगी।



शनिवार को विद्युत भवन सभागार में बिहार स्टेट पावर कंपनी व पावर ग्रिड कारपोरेशन के बीच एमओयू हस्ताक्षर के मौके पर ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, बीएसपीएचसीएल के सीएमडी पीके राय व अन्य अधिकारी